6080 मीटर जमीन पर हरियाणा सरकार से मिलकर अवैध कब्ज़ा

कैसे एम्बीयंस माल ने गुरुग्राम वन विभाग की 6080 मीटर जमींन पर हरियाणा सरकार से मिलकर अवैध कब्ज़ा कर आलीशन फ्लैट और कमर्शियल काम्प्लेक्स बना दिया। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद पर्यावरण अदालत में चल रहा केस वापस ले लिया था।

मैने और आर के शर्मा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर खुद पैरवी की और अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार , और अम्बिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को नोटिस दे तेरह मार्च को जवाब देने को कहा है। जिस जमीन पर कब्जा किया है वो सिकंदरपुर बंद और ड्रेन की है जहा से अरावली से बरसाती पानी का निकास होता है। कब्जे से नाला रुक गया और नतीजन गुरुग्राम को फ्लड का सामना करना पड़ता है। इस हमाम में सब नंगे है। सुनिए रवि यादव की रिपोर्ट। कृपया इसे सुनकर हमारा हौसला बढ़ाये।

अडानी है नई ईस्ट इंडिया कम्पनी

1857 में इंग्लैंड का गुलाम बनने से पहले, 100 साल, हम, मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंग्लैंड की एक पिद्दी सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम रहे हैं. अडानी की इंटरप्राइजेज कोयला साम्राज्य की ठगी के बारे में वाशिंगटन पोस्ट में छपी कहानी पढ़कर ये ज़िल्लत याद आ गई.

जिस सेक्रेटरी ने विरोध किया उसे हटा दिया गया. स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पुलिस ने मार-मार कर उनकी टाँगें तोड़ दीं, जेल में ठूंस दिए गए. हैरानी की बात है कि स्थानीय विधायक ने विरोध भी किया, लोगों का साथ दिया, उसे भी 6 महीने जेल में डाल दिया गया. कोई कर नहीं, कोई बिजली नहीं, हमारे हिस्से बस राख़ और धुंवा ही आएँगे!! 140 करोड़ के देश को फ़र्क नहीं पड़ा!!

उधर बांग्लादेश का सरकारी पर्यावरणविद और मंत्री कह रहा है कि हम जानते हैं कि ये योजना विनाशकारी है. हमें अभी बिजली की ज़रूरत भी नहीं लेकिन समझौते के मुताबिक जैसे ही अडानी प्लांट शुरू होगा, हम बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, हमें हर साल 450 मिलियन देना ही पड़ेगा. बिजली ख़रीदी भी तो अडानी की बिजली हमें 5 गुना मंहगी पड़ेगी. मैडम भी ये बात जानती हैं लेकिन हम तो भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं, मोदी को नाराज कैसे कर सकते हैं!!

हम एक कमज़र्फ ठग के गुलाम बन चुके हैं.

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

गुरुग्राम में घर-घर पनप रहे राज सिंह गहलौत

शहर भुगते फल्ड की मार, मेहरबानी सिकन्दरपुर बंध के कब्जाधारी

पवन कुमार बंसल

छह साल पहले मनोहर लाल ने एमजी रोड गुरुग्राम स्थित सिकंदरपुर घोसी में बरसाती नाले की सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने वालों को अभयदान दे दिया था। गुरुग्राम नगर निगम के अफसरों ने फरियाद कि की जनाब मनोहर लाल जी कब्जे नहीं हटाए तो अरावली के बरसाती पानी का निकास रुक जाएगा और गुरुग्राम की स्थिति बारिश में बेकाबू हो जाएगी। लेकिन कब्जाधारियों के प्यार में "अंधे" मनोहर लाल ने उन्हें अभयदान देते हुए ऐतेहासिक एलान किया।

"मनोहर लाल ने फ़रमाया कि चूकि ये कब्जे बहुत पुराने है और यहाँ तक कि बीस साल पुराने हो चुके है और वहां बिल्डिंग्स बन गयी है। इसलिए उन्हें उजाड़ना सही नहीं होगा। हां आगे ऐसा नहीं हो इसे रोकने के लिए राज्य स्तर पर समिति बनाई जाएगी। "

मनोहर लाल की गुड गवर्नेंस को सौ तोपों का सलाम

भूपिंदर हूडा ने भूमि अधिग्रहण का मिसयूज करके किसानो की पुश्तैनी जमीन बिल्डरों के हवाले करवाई और इसके लिए वे और उनके आधा दर्जन चहेते आईएएस अफसर अदालतों के रहम पर है। हूडा की सरकार में चेंज ऑफ़ लैंड, भूमि अधिग्रहण एक्ट का मिसयूज करने और गुरुग्राम का मास्टर प्लान बार-बार बदलने के नाम पर अरबों-खरबों का घोटाला हुआ। किसान बर्बाद हो गया और नेता, बिल्डर , टाउन एंड कंट्री विभाग और हूडा महकमे जो अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया है के अफसर रातों-रात कुबेर के खजाने के मालिक हो गए। कांग्रेस के कई नेताओं के दामाद,बेटे,बेटियां, साले और सालियां भी रातों -रात करोड़पति बन गए।

मनोहर का नाम गिनिस बुक ऑफ़ वर्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए

लेकिन जितनी बेशर्मी से मनोहर लाल ने कब्जाधारियों को अभय दान दिया उनका नाम गिनिस बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना

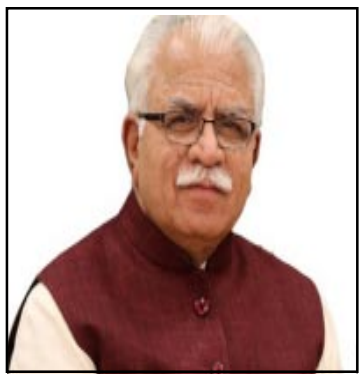

चाहिए। राज्य के सभी विश्व विद्यालय उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे। युग-युग जियो मनोहर लाल तने कर दी मौज सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने वालो की। उनकी सात पीढ़िया भी आपको याद करेगी।

"गुस्ताखी माफ़ हरियाणा" ने सरकारी रिकॉर्ड खंगाला तो कान एल्सेशियन कुत्ते की तरह खड़े हो गए और अब भी खड़े हैं।

चलो छह साल पहले। गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति की बैठक। उसमे पत्रकारों का प्रवेश वर्जित।

बैठक में तत्कालीन वन मंत्री नरबीर सिंह, तत्कालीन भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेवार तत्कालीन गुरुग्राम निगम के आयुक्त और गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर जनाब टीएल सत्यप्रकाश मौजूद थे।

मौजूद था सामाजिक कार्यकर्ता और जान जोखिम में डालकर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाला रविंद्र यादव भी। रविंद्र यादव की शिकायत का निपटारा उस दिन "आधुनिक महाराजा'' क्या मनोहर लाल के दरबार में होना था।

रविंद्र हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया कि जनाब मनोहर लाल जी, एक आठ मंजिल बिल्डिंग क्या एक ही दिन में बन गयी? वे निगम के अफसरों को लगातार शिकायत कर रहे है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जब मनोहर लाल फैसला पहले लिख कर लाए थे सो कोई क्या कर सकता था? वो तो। "महारानी" है। "महारानी" की मर्जी है चाहे कितने कपडे पहने। कोई उसे नंगा नहीं कह सकता। देशद्रोह का केस बन जाएगा।

सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सिकंदरपुर बंध से अरावली की पहाड़ियों का बरसाती पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाता है। किसान के बेटे भूपिंदर हूडा के शासन में बिल्डर माफिया को लाभ देने के लिए इस जगह सड़के बना दी गयी। लोगों ने कब्जे कर बहुमंजिला कमर्शियल इमारतें और माल बना लिए। मनोहर के मनोहर फैसले से रविंद्र यादव सदमे में आ गए थे। सूचना के अधिकार के तहत रविंद्र यादव को जानकारी मिली कि बरसाती नाले की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर बिल्डिंग बना ली है.

कब्जो से गुरुग्राम कई बार जाम का सामना कर चुका है

तीन दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा था और पूरे देश में मनोहर की किरकिरी हुई थी। पीएम ऑफिस से भी जवाब मांगा गया था और जाम से निपटने के लिए सुझाव देने के लिए मनोहर लाल ने रिटायर्ड डीजी श्रीनिवास वशिष्ठ को गुरुग्राम में विशेष अधिकारी लगाया था लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिए वो मनोहर लाल को पसंद नहीं आये और उन्हें अलविदा कर दिया गया।

गुरुग्राम सिटीजन कौंसिल के अध्यक्ष स्वर्गीय आरएस राठी भी इस मामले को उठाते रहते थे। आज तक समिति नहीं बनी और पूरे प्रदेश में मनोहर के "तुगलकी" आदेश का फायदा उठा सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। क्या विपक्ष के नेता भूपिंदर हूडा, किरण चौधरी और अभय चौटाला हरियाणा असेंबली में यह मामला उठाएंगे?

हूडा से तो कोई उम्मीद नहीं क्योंकि वो तो खुद इस हमाम में नंगे है। किरण और अभय की अग्नि परीक्षा है।

अपनी सुरक्षा राम हवाले। और अपन के पाठकों के हवाले। जब तक उनका प्यार मिलता रहेगा ये कलम चलती रहेगी।

अब बिजली वालों से पंगा लेने पर उतारू खट्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते बीसियों वर्ष से बिजली महकमें में नियमित भर्ती न करके सरकार ठेकेदारी में कर्मचारियों को लगाकर जैसे-तैसे काम को घसीट रही है। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह के कच्चे कर्मचारी अपने काम में कभी भी पूरा दिल लगा कर तन्मयता से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सदैव अपनी भविष्य की चिन्ता लगी रहती है। इसलिये वे सदैव बेहतर नौकरी की तलाश में रहते हैं।

लेकिन खट्टर यहां भी उन्हें चैन से काम नहीं करने देना चाहते। बैठे बिठाये उन्हें कौशल रोजगार निगम की सूझ गई। कोई पूछे खट्टर महाशय से कि क्या है इसका कौशल और क्या है इसका निगम और क्या है इसका रोजगार? जो लोग बीसियों वर्ष से एक सेवा देते आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि अपने नाम इस निगम में दर्ज करायें।

इस निगम के द्वारा ही उन्हें कहीं न कहीं काम पर लगाया जायेगा। मतलब करना-धरना कुछ नहीं केवल जनता को घुमनघेरी में घुमाते रहो। अच्छे-भले काम में लगे लोगों को काम से हटा कर इस निगम में भेजने का क्या तात्पर्य है? यदि यह निगम इतना ही बढिया है तथा बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम है तो राज्य में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को दर्ज करके निगम रोजगार क्यों नहीं दिलाता?

दूसरी ओर सुसंगठित एवं संघर्षशील बिजली कर्मचारियों के संगठन ने साफ-साफ घोषणा कर दी है कि वे किसी निगम में दर्ज होने नहीं जायेंगे और यदि किसी अधिकारी ने जबरन उन्हें काम से हटा कर निगम की ओर भेजना चाहा तो वे संघर्ष और हड़ताल के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। इसे लेकर बिजली कर्मचारियों ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया।

कर्मचारी यूनियन की चेतावनी का संज्ञान लेते हुए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एसई) नरेश कक्कड़ ने यूनियन प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि किसी को भी न तो काम से हटाया जायेगा और न ही किसी निगम की ओर भेजा जायेगा।